शिव टूल्ज़ इन्जीनीयरिंग की दादागीरी.....

पेज एक का शेष

है। यानी पुलिस, कम्पनी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को छिपाने तक की भी जरूरत महसूस नहीं करती। इतना ही नहीं कम्पनी के अहसानों तले दबी पुलिस ने माया की दिनांक 14 सितम्बर 2018 को दी उस शिकायत पर भी कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी जिसमें उसने एक सुपरवाइज़र व टाइमकीपर पर जबरन ओवर टाइम पर रोक कर, दिन ढले, उसकी छाती पर हाथ मार कर उस दबोचने का प्रयास किया था।

पुलिस तो पुलिस तथा श्रम विभाग भी किसी से पीछे नही रहना नहीं चाहता। माया की शिकायत पर, कई रिमांइडर देने के बाद एक श्रम निरीक्षक कम्पनी में आया और प्रबन्धक मैडम के साथ चाय-नाश्ता करने बैठ गया। खूब खा-पी कर जेब में दो-दो हजार के दो नोट डालने के बाद उस हरामखोर ने शिकायतकर्ता माया को बुलाया और अपनी नमक हलाली दिखाते हुये उल्टे माया को ही धमकाने लगा। ग्यारह हज़ार वेतन सुन कर उस निरीक्षक ने मैनेजर मैडम से कहा कि सरकारी वेतनमान तो नौ हज़ार है, जब इनको इतना फ़ालतू वेतन मिलेगा तो ये बिगड़ेंगे ही। इसी तरह पीएफ़ वाले भी तमाम शिकायतों के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं। जाहिर है वे भी चुपचाप अपना चुग्गा-पानी वसूल ही रहे होंगे।

अन्त में दुखी होकर माया, कुछ स्थानीय भाजपाई एंड ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ, यहां दौरे पर आये श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी से मिली और अपनी फ़रियाद सुनाई। माया यह देख कर खुश हो गयी जब मंत्री ने तुरंत उप श्रमायुक्त को बुला कर उन्हें डांटा तथा माया को शीघ्र न्याय दिलाने की बात कही लेकिन बीस दिनों बाद भी माया की समस्या जहां थी वहीं है बल्कि अब उसे काम से भी निकाल दिया गया है।

खाई हुई रिश्वत का हक ऐसे अदा किया

पीड़िता माया की शिकायत पर बिकी हुई पुलिस ने जब कोई कार्यवाही नहीं की तो महिला नेता जगजीत कौर पन्नू के नेतृत्व में दिनांक 28 सितम्बर को महिलाओं ने डबुआ थाने पर करीब तीन घंटे जम कर प्रदर्शन किया व पुलिस विरोधी नारे लगाये। इस प्रदर्शन के परिणामस्वरूप वहां महिला पुलिस को बुलाया गया, पीड़िता का ब्यान लेकर धारा 354, 506 आईपीसी के अन्तर्गत एफ़आईआर नम्बर 74 दर्ज करके आरोपी महेन्द्र इन्चार्ज को गिरफ़्तार कर लिया गया। मैजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 का ब्यान दिनांक 29 सितम्बर को दर्ज कराया जायेगा। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने फ़ैक्ट्री के उस स्थान का निरीक्षण किया जहां माया के साथ अभद्रता हुई थी।

कम्पनी मालिक की कृपाओं के बोझ तले दबी जो पुलिस पीड़िता के साथ ठीक ढंग से बात तक नहीं करती थी, उसके पिता को 'गैट आउट' बोलती थी, अब एफ़आईआर तक दर्ज करने को मजबूर हो गयी। लेकिन खाई हुई रिश्वत का हक अदा करते हुये पुलिस ने आरोपी महेन्द्र से 14 सितम्बर की तारीख में माया के विरुद्ध एक शिकायत ले ली। इसमें कहा गया है कि माया 30-35 गुंडे लेकर आई थी और अवैध रूप से फ़ैक्ट्री में घुस कर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस फ़र्जी शिकायत पर माया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147,149,323,452, व 506 के अंतर्गत एफ़आईआर नम्बर 75 दर्ज कर ली है।

इसी को तो कहते हैं पुलिस द्वारा रस्सी का सांप और सांप का रस्सी बनाना।

इलाज भले ही न मिले.....

पेज एक का शेष

इस अवसर पर उनके 7 मिनट के ढीले भाषण व उनकी बॉडी लेंग्वेज यह स्पष्ट बता रही थी कि जिस 'आयुष्मान' योजना को वे जनता को समर्पित कर रहे हैं, वह कतई नकली एवं दिखावा मात्र है। लम्बा-चौड़ा भाषण देने के शौकीन गूजर ने अपने इस छोटे से भाषण में केवल उन्हीं रटे-रटाये शब्दों का प्रयोग किया जो मोदी जी ने उसी वक्त छत्तीसगढ़ में बोले थे।

भीतरी तौर पर तो गूजर यह भी जानते हैं कि यह ड्रामा केवल आगामी चुनावों तक खींचने के लिये किया जा रहा है। किसी तरह एक बार चुनाव अधिसूचना जारी होने यानी आचार संहिता लगने तक पहुंच जायें तो आगे फ़िर कुछ करने की जरूरत नहीं। तब तक इस 'आयुष्मान' का ढोल पीटा जाता रहेगा। लोग पागलों की तरह एक लाइन से दूसरी लाइन, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर तक के चक्कर काटते रहेंगे। इस बीच कुछ गिने-चुने मरीज़ों का इलाज करके मोदी जी उनसे एक नकली सा प्रायोजित संवाद मीडिया में उछालते रहेंगे।

परन्तु ज़मीन से जुड़े कृष्णपाल यह बखूबी समझते हैं कि मोदी जी का तो भले ही इस ड्रामे से काम चल जाय, परन्तु उनका काम नहीं चलने वाला। उनके यहां तो हर रोज़ सीधे चल कर इलाके से लोग आ बैठेंगे, वे किस-किस का इलाज करायेंगे, बड़ी संख्या में इलाज के लिये आमंत्रित जनता से वे कैसे निपटेंगे, किस-किस को कितनी बार झूठ बोलेंगे? यही सब प्रश्न हैं जिनसे बहुत जल्द मंत्री जी को दो-चार होना है। इसी को लेकर वे परेशान नज़र आये।

वैसे भी कृष्णपाल इस बात को बखूबी समझते हैं कि मरीज़ों को बेहतरीन इलाज देने के लिये और अधिक अस्पतालों व डॉक्टरों की जरूरत है न कि इस तरह की नौटंकियों की। जितना धन इस नौटंकी व इसके प्रचार पर खर्च किया जा रहा है, उसे यदि चिकित्सा सेवाओं के विस्तार पर खर्च किया जाता तो कहीं अधिक लाभ हो सकता था।

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी की डिग्री का खुलासा कब होगा

डिग्री स्कैन्डल में स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री द्वारा त्याग पत्र

मज़दूर मोर्चा के 23-29 सितम्बर 2018 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक व साहित्यिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुये हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2019 में होने हैं। परन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अभी से चुनावी रंग में आ चुके हैं और जहां भी किसी सभा या रैली को सम्बोधित करते हैं वे अपनी सरकार की साढ़े चार साल की तथाकथित उपलब्धियों की फेहरिश्त सुनाने में लग जाते हैं। उनमें से कुछ योजनायें तो ऐसी होती हैं जिनका लोकापर्ण तो मोदीजी ने पहले ही कर दिया था परन्तु अभी तक धरातल पर मूर्तरूप नहीं ले सकी है।

मोदीजी जब बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के एम्फीथियेटर मैदान में आयोजित सभा में भाषण देते हुये अपनी उपलब्धियां गिनाते हुये चार साल का हिसाब दे रहे थे और बनारस (काशी) की जनता को अपना मालिक और हाईकमान बता रहे थे उसी दौरान जनता का कुर्सी छोड़कर पंडाल से बाहर जाने का सिलसिला लगातार चलता रहा। इससे निराश होकर मोदी जी को अपना भाषण बंद करना पड़ा, जिसका 'सिंहासन खाली करो नरेन्द्र मोदी!' में पूरा विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त रविवार को भाजपा ने दिल्ली पूर्वांचल मोर्चे के तले रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया जिसको अमितशाह ने सम्बोधित किया। इस रैली में 75000 लोग़ों की भीड़ आने का दावा किया गया था परन्तु केवल 10000-12000 लोग पहुंचे। इससे मोदीजी और शाह दोनों को अहसास हो गया कि उनकी लोकप्रियता व विश्वसनीयता कम होती जा रही है और उन्हें चुनाव में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रीय सेवक संघ (संघ), भाजपा तथा मोदी सरकार सभी सबका साथ सबका विकास तथा सामाजिक समरसता की बातें तो बहुत करते हैं, परन्तु मोदी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में हिन्दुओं द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोग़ों के उत्तपीड़न व यातनाओं की घटनाऐं लगातार हो रही हैं। 'रोहतक पंचायत ने मुसलमानों के टोपी पहनने, दाढी रखने और नमाज पढने पर लगाई रोक' में रोहतक पंचायत द्वारा मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित धोबी समाज के मुसलमानों पर टोपी पहनने, दाढ़ी रखने, सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने, बच्चों के उर्दू अरबी नाम रखने पर प्रतिबंध लगाने के तालिबानी फ़ैसले का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। भाजपानीत खट्टर सरकार के काल में यह सहिष्णुता, लोकतंत्र व न्यायिक प्रणाली और सभी धर्मों के बराबरी की नज़र से देखने वाली सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात है तथा पंचायत का यह तुगलकी फैसला अमानवीय और असंवैधानिक है जिसको लोकतान्त्रिक सभ्य समाज में मान्यता नहीं दी जा सकती। पूंजीपति अपनी व्यवसायिक गतिविधियां व व्यवसायिक उपक्रम उपस्थित करने व चलाने के लिये अपने पास से अपनी पूंजी न लगाकर बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपये कर्ज़ लेकर निवेश करते हैं। यदि वह उपक्रम नहीं चल पाता तो पूंजीपति बैंक के कर्जे का भुगतान करने की अपेक्षा उस राशि को विदेशों में भेजकर वहां निवेश कर देते हैं। और विदेश चले जाते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, चोकसी की तरह गुजरात का व्यवसायी नितिन संदेसरा (स्टालिंग बायोटेक का मालिक) भी 5 हजार करोड़ रुपये का बैंक घोटाला करके परिवार सहित नाइजीरिया चला गया है। यही कर्ज़ ब्याज समेत एनपीए बनता जाता है जो सुरसा के मुख की तरह बढकर लगभग 12 लाख करोड़ हो चुका है, जिसका 'खबर (दार) झरोखा-पूंजिपतियों की संपत्ति में इजाफ़े का खेल है एनपीए' में विवेचन किया गया है। कर्ज़ न चुकाने से जहां बैंकों का एनपीए बढता है वहीं पूंजीपति का कोई नुक्सान नहीं होता उल्टा कर्ज़ न चुकाने पर भी उसकी पूंजी बढती जाती है। पूंजीपति, बैंक व सरकार की मिलीभगत का ही नतीजा एनपीए है।

भारतीय प्रजातंत्र की विलक्षणता है कि आम आदमी चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर सकता। दबंग और अरबपति अपनी धौंस व धन शक्ति के बल पर चुनाव जीतकर विधानसभा व संसद पहुंच जाते हैं। राज्य सभा के चुनाव में भी धन बल पर विधान सभा के विधायकों के मत खरीदकर राज्य सभा पहुंच जाते हैं। ऐसे सांसदों के लिये कानून व न्याय व्यवस्था का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य केवल धन बटोरना होता है।'अरबों रुपये लुटाकर जो संसद पहुंचा, वह देश लूटेगा ही, में किंग फिशर के मालिक विजय माल्या का धन बल से कर्नाटक से राज्य सभा का सदस्य बनने तथा बैंक का कर्ज़ा चुकाने की बजाय लंदन भाग जाने के संदर्भ में इस व्यवस्था का सटीक विश्लेषण किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में रमणसिंह की भाजपा सरकार ने नक्सलियों से निपटने और आदिवासियों की सुरक्षा के नाम पर सीआरपीएफ़ की नयुक्ति कर रखी है। लेकिन सीआरपीएफ़ के जवान दारू पीकर सुरक्षा के नाम पर कैम्पों से निकलते हैं और आदिवासी महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण है दन्तेवाड़ा ज़िले के समेली गांव में नाबालिग आदिवासी लड़की का बलात्कार। दन्तेवाड़ा का पुलिस प्रशासन बदनामी से बचने के लिये इस मामले को दबाने में लगा हुआ है, जिसका 'होश में आते ही नाबालिग आदिवासी लड़की बोली सीआरपीएफ़ जवानों ने किया है बलात्कार' तथा 'छत्तिसगढ़ दन्तेवाड़ा ज़िले के समेसी गांव में सीआरपीएफ़ कैम्प है बलात्कार के पीछे' में पूरा खुलासा किया गया है। छत्तीसगढ में मोदी सरकार का महिला सशक्तिकरण का नारा खोखला साबित हो रहा हे जहां रमणसिंह की सरकार आदिवासी महिलाओं के बलात्कार की रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही नहीं करती।

मोदी सरकार ने स्वछता अभियान के प्रचार और टॉयलेट बनाने की योजना पर काफ़ी धन राशि आवंटित की है परन्तु समाज के जिस वर्ग (वाल्मिकी) पर स्वच्छता का दायित्व है उसकी अवहेलना की जा रही है। सीवर साफ़ करने वाले श्रमिकों की दशा तो और भी अमानवीय हो रही है। आधुनिक युग में भी सीवर की सफ़ाई अक्सर मशीनों से नहीं की जाती। परम्परागत सफ़ाईकर्मी खुद सीवर में न उतरकर ठेके पर काम करने वाले अथवा कैजुअल आदमी को सीवर में उतार देते हैं। सफ़ाई के लिये उनको न तो वांछित सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, हेल्मेट, गैस मास्क आदि दिये जाते हैं और ना पर्याप्त मज़दूरी दी जाती है। मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर गटर सफाई के लिये जरूरी उपकरण मुहैया कराये जायें, परंतु सरकारें इस आदेश की खुली अवहेलना कर रही हैं, जिसका 'गटर में सड़ते भारत को बचाने वाले शहीदों को न हर्जाना न उनका कोई शोक' में पर्दाफ़ाश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गटर गैस से चाय बनाने के बयान की 'गटर गैस से चाय नहीं बनती मोदीजी, जान निकलती है' में पोल खोली गयी है। गटर गैस में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड जैसी गैस होती हैं जिनके शरीर में जाने से जान चली जाती हैं। सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 1993 से अब तक 1370 तथा पिछले सात दिनों में 11 सीवर श्रमिकों की सीवर में मृत्यु हो चुकी है। यदि वास्तव में मोदी सरकार स्वछता अभियान को सफ़ल बनाना चाहती है तो टीवी चैनलों व मीडिया में प्रचार की जगह सफ़ाई कर्मियों व सीवर श्रमिकों की दशा में सुधार करे और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश को सख्ती से लागू करे।

डिग्री स्कैन्डल में स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री द्वारा त्याग पत्र देने और भारत की केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी द्वारा उनकी विवादित शैक्षणिक योग्यता मामले में त्यागपत्र न देने पर 'स्पेन' हेल्थ मिनिस्टर क्विट्स ऑवर डिग्री स्कैन्डल डॉन्ट लुक एट मी, आई एम फ्रॉम इंडिया' कार्टून द्वारा स्मृति इरानी पर उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।